Page No.1

राजस्थान विधान सभा

बुधवार, दिनांक २४ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

राजस्थान के राज्यपाल, श्री गुरमुख-निहालसिंह, का अभिभाषण

(राज्यपाल महोदय के अभिभाषण देने हेतु खड़े होने पर करतल–ध्वनि)

राज्यपाल (श्री गुरमुखनिहालसिंह) : अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य गण,

विधान सभा के इस नये सत्र में इस बार पुनः आपका स्वागत करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है ।

२. पिछले वर्ष में राज्य सरकार तथा यहां के लोग राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयत्न में निरन्तर जुटे रहे हैं । उत्पादन के तरीके में तकनीकी ज्ञान का फायदा उठाने तथा अपनाने की जरूरत लगातार महसूस की जाती रही है । स्थानीय वैधानिक संस्थाओं को सत्ता सौंप देने का जो साहसिक एवं दूरदर्शिता पूर्ण फैसला किया गया उसका सर्वत्र स्वागत हुआ है और इससे सारे देश में प्रशंसा हुई है । हमारे इस कदम की तरफ दुनियां के दूसरे देशों में भी दिलचस्पी पैदा हुई है ।

३. यह बड़ी खुशी की बात है कि जनता और इन संस्थाओं के नुमाइन्दों ने अपनी जिम्मेवारी आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ सम्भाली है । जनता के नुमाइन्दों और राज्य कर्मचारियों के बीच जो सम्बन्ध पैदा हुए हैं वे इन संस्थाओं के उज्ज्वल भविष्य के सूचक हैं । मतदाता कौंसिलें जिनकी बैठकें कम से कम वर्ष में दो बार हुआ करेंगी, जनता और उसके नुमाइन्दों के बीच परस्पर सहयोग की भावना पैदा करेंगी। मुझे विश्वास है कि कुछ समय के बाद इन संस्थाओं द्वारा नीति और प्रोग्राम बनाये जाने में ये कौंसिलें काफी प्रभावशील होंगी । मुझे यह कहने की जरूरत नहीं कि इस व्यवस्था से, ग्राम जीवन में व्याप्त पारस्परिक मतभेद तथा गुटबन्दियां, यदि पूरी तरह समाप्त नहीं भी हुई तो बहुत हद तक कम अवश्य हो जायेंगी ।

४. पंचायत राज्य की सफलता के लिये विकास सम्बन्धी कार्यों के विभिन्न पहलुओं और उनसे सम्बन्धित अन्य मसलों का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है । इस

Scanned by CamScanner

Page No.2

(श्री गुरमुखनिहालसिंह)

हेतु जनता, उसके नुमायन्दों, स्थानीय संस्थाओं के मुलाजिमों तथा सरकार के स्थाई कर्मचारियों की ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम कार्यान्वित किये गये हैं उनका नतीजा बड़ा अच्छा हुआ है। इन संस्थाओं के सदस्यों के प्रशिक्षण के हेतु राज्य में ५ केन्द्रों पर व्यापक अध्ययन कार्यक्रम की व्यवस्था स्थाई तौर पर की गई है और उसे पंचायत प्रशासन का स्थाई अंग बना दिया गया है। इन संस्थाओं, सरकार तथा उसके विविध अंगों को इन संस्थाओं की प्रतिक्रियाओं तथा ऐसी समस्याओं के बारे में जो पेश आवें, जानकारी मिलती रहे इस विचार से राज्य में एक मूल्यांकन संगठन कायम करने का निश्चय किया गया है। यह संगठन मसूरी में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एण्ड रिसर्च ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट से निकट सम्पर्क रखते हुए कार्य करेगा। यह संगठन इस बात का मूल्यांकन करेगा कि जनता ने इन प्रोग्रामों को किस हद तक अपनाया है और उसका उनके प्रति कैसा रुख रहा है तथा उनका जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा है। इन संस्थाओं के मसलों पर जनता के नुमाइन्दों के साथ विचार करने के लिए जिला हैडक्वार्टर्स पर मंत्रि-मण्डल की बैठकें करने का जो निर्णय हुआ है उससे उन लोगों में काफी दिलचस्पी पैदा हुई है और उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिला है। मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार के सदस्यों का यह सीधा सम्पर्क इन संस्थाओं को मजबूत बनाने तथा प्रशासन के विविध अंगों के बीच गहरे सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होगा।

५. विविध क्षेत्रों में जो कामयाबी मिली है और जिस तरीके से पंचायत समितियों ने अब तक कार्य किया है उसका निष्पक्ष मूल्यांकन करने की व्यवस्था की जा रही है और जिन पंचायत समितियों ने उल्लेखनीय कार्य किया है उन्हें विशेष अनुदान तथा ऋण देने की भी व्यवस्था की गई है। यह भी तय किया गया है कि मालगुजारी वसूल करने की जिम्मेवारी भी धीरे धीरे पंचायत समितियों को सौंप दी जाय जो सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करेंगी। ऐसी तजवीज है कि जो पंचायत समितियां अपने कार्य में एक निश्चित सीमा तक कुशलता और कामयाबी हासिल कर लें, उन्हें अगले साल यह अधिकार दे दिये जायं।

६. लोकतांत्रिक व्यवस्था को आर्थिक आधार देने के लिये यह फैसला किया गया है कि पिछले वर्ष जो स्वायत्त संस्थायें बनाई गई थीं वे अपनी अपनी विकास योजनायें तैयार करें, और उन योजनाओं को राज्य की योजना में विशिष्ट स्थान दिया जाय। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्ताव तैयार करने के तरीके पर विचार किया जा रहा है। ये योजनायें राष्ट्रीय पालिसी तथा स्टेट प्लान की रूपरेखा के अन्तर्गत तो रहेंगी ही, साथ ही पंचायत समिति प्लान, जिला प्लान तथा स्टेट प्लान से भी सम्बन्धित होंगी।

७. पंचायत समितियां कृषि उत्पादन के कार्यक्रम में सक्रिय भाग लें, इसलिए यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक पंचायत समिति अपना खुद का एक फार्म रखेगी जो कि उस क्षेत्र का मोडल फार्म होगा। सरकार, जहां आवश्यकता होगी पंचायत समितियों को भूमि दिलाने में भी मदद करेगी।

८. इस ख्याल से कि देहाती जनता में

Scanned by CamScanner

Page No.3

(श्री गुरमुखनिहालसिंह)

अधिक पारस्परिक सम्पर्क पैदा हो जाय, यह तय किया गया है कि पंचायतों का क्षेत्र कम कर दिया जाय और पंचायतों का इस प्रकार पुनःगठन किया जाय कि उनका क्षेत्र, जहां तक हो सके, पटवार सर्किल के अनुरूप रहे। इससे ग्रामस्तर पर शासन का स्थायी ढांचा कायम हो जायेगा। यह भी तय किया गया है कि जुडिशियल काम के लिये अलग पंचायतें बनाई जायं। इस बारे में सदन के इसी सैशन में आवश्यक कानून पेश किया जायेगा।

९. सरकार नगर सामुदायिक विकास प्रोग्राम के सवाल पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए स्कीमें तैयार करने हेतु वर्किंग ग्रुप बना दिये गये हैं। इससे म्युनिसिपैलिटियों को और अधिक अधिकार देना आवश्यक हो जायेगा जो कि विचाराधीन है। सर्वतोमुखी विकास तथा एरिया प्लानिंग के लिए किसी न किसी स्तर पर यह आवश्यक होता है कि सभी स्थानीय निकाय अपने अपने कार्यक्रमों को एक सूत्र में बांध लें। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि जिले में जिस म्युनिसिपैलिटी की अनुमानित जनसंख्या एक लाख से कम हो, उसके अध्यक्ष को वहां की जिला परिषद् का सदस्य बनाया जाय।

१०. सुदूरव्यापी तथा उच्च-लक्ष्य की ओर उन्मुख तीसरी पंचवर्षीय योजना का फ्रेम और उसकी रूपरेखा तैयार करने के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है और उसका एक प्लान-फ्रेम सरकार का योजना विभाग जारी भी कर चुका है। तीसरी योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन—जिसकी योजना इस आधार पर बनाई गई है कि वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में मिल सकें—की ओर अधिक ध्यान देना और राज्य के ऐसे विभिन्न भागों में उद्योगों की स्थापना करना है जहां बिजली तथा आवश्यक कच्चा माल सस्ता मिल सके। राजस्थान की प्यासी भूमि के लिए सिंचाई का सुविधाजनक इंतजाम करना, सस्ती दर पर बिजली प्राप्त करने के साधनों का यथासंभव विकास करना, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की वैधानिक जिम्मेवारी को पूरा करना, राज्य के पशुधन की उन्नति करना और टेक्नोलाजी जिसका राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विविध पहलुओं से अभिन्न रूप से सम्बन्ध है, का विकास करना कुछेक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके लिये आगामी योजना-काल में प्रयत्न करना है। इन कार्यों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता तथा उनके प्रशिक्षण को हर वक्त ध्यान में रखा गया है। विभिन्न "मैन पावर" समितियों की रिपोर्ट सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इसका अंतिम रूप, विभिन्न वर्किंग ग्रुपों तथा प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्टों पर विचार करने और योजना आयोग के साथ सलाह मशविरा करने के पश्चात् ही निश्चित किया जा सकेगा।

११. इंडस्ट्रियल एंड इकोनोमिक स के कार्यालय द्वारा किये जा रहे विस्तृत सर्वे के अतिरिक्त, राज्य का शीघ्र टैकनो-इकोनोमिक सर्वे करने का कार्य, नेशनल कौन्सिल आफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च को सौंपा गया है। इस कौन्सिल द्वारा तैयार की गई सर्वे की रिपोर्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहायक होगी।

१२. पुनर्गठित राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए १०५.२७ करोड़ की राशि रखी गई थी। चालू वित्तिय वर्ष के अन्त तक ७२.०६ करोड़ का खर्चा हो

Scanned by CamScanner

(श्री गुरमुखनिहालसिंह)

जायगा । १९६०-६१ वर्ष के लिए योजना-लागत २८.२० करोड़ रू० होगी । यह लागत राजस्थान नहर के लिए अपेक्षित राशि के अलावा होगी । गत वर्ष के लिए रखी गई २०.१२ करोड़ की कुल राशि में से १९.९७ करोड़ का खर्च हुआ जो योजना-लागत के ९९ प्रतिशत से कुछ ज्यादा है ।

१३. सामुदायिक विकास योजना के कार्य-क्रम में न केवल लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति ही कायम रही है बल्कि पंचायत समितियों के बन जाने से प्रगति और भी अधिक तेजी से हो रही है ।

१४. पशुओं की विभिन्न नस्लों के सुधार, उनमें फैली हुई बीमारियों का इलाज तथा नियन्त्रण और पशु धन उप-उद्योगों के निर्माण, लाइवस्टाक पब्लिक युटिलिटी सर्विसेज की स्थापना और उनको चलाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की ट्रेनिंग आदि कार्यों में संतोषजनक प्रगति हुई है ।

१५. हर्ष का विषय है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के चौथे वर्ष में हम द्वितीय योजना काल के लिए निर्धारित ८.१२ लाख टन अतिरिक्त अनाज उत्पन्न करने के लक्ष्य से अधिक अनाज पैदा कर सकेंगे । ऐसा अनुमान है कि मार्च, १९६१ के अन्त तक हम करीब करीब १२ लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा कर सकेंगे ।

१६. एग्रोनोमिकल, इंजीनियरिंग और फोरेस्ट्री प्रेक्टिसेज़ के डिमॉन्सट्रेशन के लिए १००० एकड़ के दो खंडों में, दो पायलट प्रोजेक्ट का कार्य शुरू किया गया है । जोध-पुर में एक लेबोरेटरी कायम की गई है जिसमें मिट्टी की जांच जल्द की जा सकेगी और कृषि के बढ़िया औजार बनाने के लिए जयपुर में एक वर्क-शाप स्थापित किया जा रहा है ।

१७. सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है और चम्बल नदी पर होने वाला निर्माण-कार्य भी इस वर्ष शुरू कर दिया गया है । १३४ मील लम्बी राजस्थान फीडर चैनल के निर्माण-कार्य में अच्छी प्रगति हुई है । फीडर पर चिनाई के तीन बड़े कार्य पूरे हो गये हैं और दूसरे २० काम चल रहे हैं । फीडर को पक्का बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है । प्रोजेक्ट तथा प्रोजेक्ट-क्षेत्रों के सम्पूर्ण सर्वतोमुखी विकास, जिसमें सिंचाई, भूमि विकास, सड़कें, रेलें, उद्योग तथा मार्केटिंग सेन्टर्स शामिल हैं, के लिए एक "मास्टर प्लान" तैयार किया जा रहा है । चम्बल प्रोजेक्ट से मिलने वाले पानी का अधिक से अधिक लाभ उठाने और पानी मिलने पर उसे जल्दी से जल्दी काम में ले लेने के लिए सिंचाई क्षेत्रों में विकास प्रोग्रामों के अन्तर्गत खेती सम्बन्धी स्पेशल रिसर्च का काम शुरू कर दिया गया है । ऐसे ही कदम राजस्थान नहर क्षेत्र में भी उठाये जा रहे हैं ।

१८. पानी के उपलब्ध सभी साधनों को यथाशीघ्र उपयोग में लाने के लिये, सिंचाई के साधनों का नियमित एवं व्यापक सर्वे व जांच आवश्यक है । इस साल इस काम के लिए १३ और एसिस्टेंट इंजिनियरों की नियुक्ति की गई है और उन्हें इसके लिए जरूरी स्टाफ और सामान भी दिया गया है । इससे हम सिंचाई के छोटे छोटे निर्माण कार्य और एनीकट बनाने की तरफ और भी अधिक ध्यान दे सकेंगे ।

Scanned by CamScanner

Page No.5

(श्री गुरमुखनिहालसिंह)

१६. बिजली सप्लाई करने के काम में अच्छी तरक्की हुई। भाखरा से पहली बार बिजली पिलानी को मई, १६५६ में और श्री गंगानगर को जनवरी, १६६० में दी गई। राजगढ़ को फरवरी, १६६० के आखिर तक या मार्च के पहले पखवाड़े तक बिजली मिलने लगेगी और वहां से रतनगढ़ और उन सारी जगहों को बिजली मिल सकेगी जिन्हें अब बीकानेर से बिजली मिलती है। इससे बीकानेर पावर हाउस से बिजली सप्लाई का बोझ काफी कम हो जायगा। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से राजस्थान के भीतर बिजली वितरण-व्यवस्था का बहुत कुछ काम पूरा कर लिया गया है और बाकी काम अगले वर्ष में पूरा कर लिया जावेगा। चंबल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में बहुत कुछ जरूरी सामान की खरीद के लिए आर्डर दे दिये गये हैं। जयपुर-सवाईमाधोपुर लाइन पर खंभे गाड़ने के काम में काफी तरक्की हुई है। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट जो कि चंबल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है. प्लानिंग कमीशन द्वारा मंजूर कर लिया गया है। इस पर १७,०० करोड़ रुपये से ज्यादा खर्चा होगा और इस प्रोजेक्ट के बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।

२०. कोपरेटिव सोसाइटियों की संख्या जो पहले १०,५३१ थी अब १२,३६४ हो गई है और उनके मेम्बरों की संख्या जो पहिले ४,५३,२७१ थी अब ५,६६,६७४ हो गई है। शेयर केपिटल २.०० करोड़ से ३.०० करोड़ और वर्किंग केपिटल १२ करोड़ से १७ करोड़ हो गई है। सर्विस कोपरेटिव सोसाइटीज कायम करने में अच्छी तरक्की हुई है जिनकी संख्या अब १,७८५ हो गई है। इस साल के दौरान में ५४२ कोपरेटिव फार्मिंग सोसाइटियां भी कायम की गई हैं।

२१. पिछले साल राजस्थान में काफी औद्योगिक तरक्की हुई। कोटा में नाइलोन फैक्टरी और उदयपुर में स्पिनिंग मिल चालू करने के लिए इंतजाम किया गया है। सवाईमाधोपुर में डिज़ल लोकोमोटिव फैक्ट्री चालू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर में नये तौर पर चालू की गई वैगन फैक्टरी ने भी वैगन तैयार करने में काफी तरक्की की है। राजस्थान में टैक्सटाइल उद्योग को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए एक टैक्सटाइल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। डीडवाना में ब्राईन (नमक का घोल) से सोडियम सल्फेट बनाने के लिए पायलट प्लांट कायम करने का सवाल आखिरी तौर पर तय हो गया है और ६.८ लाख रुपये की मशीनरी बाहर से मंगाने के लिए लाइसेंस मंजूर कर दिया गया है। यह प्लांट रोजाना २० टन सोडियम सल्फेट तैयार करेगा। आपको यह जानकार खुशी होगी कि फर्टीलाइजर फैक्ट्री के लिए स्थान के बारे में सिफारिश करने के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी उसने हनुमानगढ़ में फैक्ट्री बनाने के हमारे दावे का समर्थन किया है।

२२. इन्डस्ट्रियल एस्टेट संबंधी स्कीम में भी काफी तरक्की हुई है और जयपुर में बनाये गये २४ शैड अलग अलग उद्योगों को बांट दिये गये हैं। इनके अलावा २४ शैड और तैयार होने वाले हैं। जोधपुर, उदयपुर, और सुमेरपुर में भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम करने के लिए बहुत जल्दी कार्रवाई की जायेगी। इनके अलावा अलवर, धोलपुर, पाली, गंगापुर और बीकानेर में

Scanned by CamScanner

(श्री गुरमुखनिहालसिंह)

पांच और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम करने के लिए फैसला किया है । अभी अभी सरकार ने कुछ रियायतों की व कर्जा देने के नियमों को उदार बनाने को, घोषणा की है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि इन सुविधाओं के कारण औद्योगिक विकास और भी अधिक तेजी से हो सकेगा ।

२३. खादी और हाथ करघा कपड़े के उत्पादन में लगातार तरक्की हुई है ।

२४. राजस्थान विविध औद्योगिक खनिज-पदार्थों तथा खनिज-चट्टानों से सम्पन्न है। अलवर, खेतड़ी तथा खोह दरीबा में हाल में जो जांच की गई है उससे यह साबित हो गया है कि उस क्षेत्र में एक लंबी खनिज-पट्टी है। सन् १९५९ में राज्य से ८४,६०० टन कच्चा लोहा निर्यात किया गया। अणु शक्ति विभाग की देखरेख में विभिन्न स्थानों पर रेडियो-एक्टिव खनिजों के लिए सविस्तार खोज व जांच की जा रही है। राज्य में विभिन्न रेडियो-एक्टिव खनिजों के काफी अच्छी तादाद में पाये जाने के संकेत मिले हैं। जैसलमेर क्षेत्र में ऐसे स्थानों के बारे में भी अनुसंधान किये गये हैं जहां तेल मिलने की संभावना है। डूंगरपुर क्षेत्र में फ्लोरस्पार (fluorspar) के बड़े डिपोज़िट का पता चला है। राज्य में अन्य उपयोगी खनिज पदार्थों की खोज भी जारी है। राज्य में सन् १९५९ में खनिज उत्पादन की धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है और कुल मिला कर ५.०० करोड़ रु० का खनिज उत्पादन हुआ।

२५. सन् १९५९-६० में शहरी इलाकों में पानी सप्लाई करने की ६० योजनाओं पर १९६.०० लाख रु० खर्च किया जायगा। पुराने कुओं की मरम्मत, नये कुओं के निर्माण तथा अन्य छोटे-मोटे सुधार के कार्यों पर करीब ६० लाख रु० खर्च किया जायगा। ये कार्य पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के जरिये पूरे कराये जायेंगे। राज्य में पीने के पानी संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार उस पर विचार कर रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस मसले को हल करने के लिए काफी रकम रखने का प्रस्ताव है।

२६. तीसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए सभी स्थानों पर निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा का जो राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है वह राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नये प्राइमरी स्कूल खोलने का जो लक्ष्य रखा गया था हम उससे आगे बढ़ गये हैं। पिछले दो सालों में बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में भर्ती करने के सिलसिले में जो आन्दोलन किये गये थे उनके बहुत अच्छे नतीजे रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा का विस्तार करने के उत्साह-वर्धक प्रोग्राम को पूरा करने के लिए इस साल ११ बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल खोले गये, जिनमें से प्रत्येक स्कूल में शुरू में १०० विद्यार्थी-अध्यापकों के दाखिले की व्यवस्था है। अब इन स्कूलों की संख्या ३८ हो गई है। अगले साल में २१ टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल और खोलने का प्रस्ताव है। ऐसा ख्याल है कि तीसरी योजना के दौरान में इन स्कूलों में पूरी तौर से ट्रेनिंग पाये हुये इतने अध्यापक मिल सकेंगे कि मौजूदा स्कूलों व तीसरी योजना में खोले जाने वाले प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की जरूरत पूरी की जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

(श्री गुरमुखनिहालसिंह)

कालेज के अध्यापकों की वेतन-श्रेणियां इस तरह तब्दील करदी गई हैं कि वे प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले आफिसरों के बराबर हो जायं। यह उम्मीद की जाती है कि राज्य की शिक्षा-सेवा में अब न सिर्फ राज्य के ही बल्कि सारे देश में से अधिक से अधिक योग्य व्यक्ति आकर सर्विस करने को उत्सुक होंगे और कार्य करते रहेंगे।

२७. अलग अलग श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों में अध्ययन तथा रिसर्च करने की आदत को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने एक योजना मंजूर की है जिसके अनुसार सरकार अपने कर्मचारियों को विविध विषयों पर लेख या किताबें लिखने के लिए नकद इनाम देगी। यह भी प्रस्ताव है कि अध्यापन-कार्य और अन्य टेकनिकल तथा प्रोफेशनल सर्विस में नियोजित व्यक्तियों को तरक्कियां व स्पेशल मेरिट-ग्रेड देकर पुरस्कृत किया जाय। कुछ कमेटियां ऐसी बनादी गई हैं जो उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा किये गये काम की जांच करके सरकार को रिपोर्ट पेश करेंगी कि क्या इनाम दिये जाने चाहियें।

२८. अन्य विकास सैक्टरों में प्रगति का रुख वृद्धि की ओर ही रहा है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं में संतोष-जनक प्रगति हुई है।

२९. स्टाफ को, जिसमें चौथी श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं, मकान सम्बन्धी सुविधाएं देने की दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के सरकारी नौकरों के रहने के लिए १९५९-६० में कई स्थानों पर मकान बनाने की मंजूरी दी गई।

३०. सरकारी दफ्तरों में नौकरी चाहने वाले क्लर्कों के लिये इस साल डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया और उम्मीद है कि इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार सरकारी विभागों में अधिक उपयोगी साबित होंगे। यह कोर्स ६ स्थानों पर चालू किया गया है।

३१. सरकार, भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यों की ओर बराबर ध्यान देती रही है और जोतों (Holdings) की अधिकतम सीमा नियत करने के बारे में कानून पास हो जाने की वजह से इन सुधारों की रफ़्तार और तेज हो जायगी।

३२. जमीन्दारियों और बिस्वेदारियों को खत्म करने और जागीरों को खालसा करने का काम और भी आगे बढ़ा है। कुल २,४५,६४० जागीरें खालसा कर दी गई हैं और जमींदारी तथा बिस्वेदारी के सब अधिकार खत्म कर दिये गये हैं। जागीरदारों को फिर से बसाने के काम में भी इस वर्ष में संतोषजनक प्रगति हुई है।

३३. पिछले दो सालों में जोतों का एकीकरण (Consolidation) करने के काम में भी तेजी आई है। कुल ७.५१ लाख एकड़ जमीन का एकीकरण हो चुका है।

३४. इस वर्ष में लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत संतोषप्रद रही। डाकुओं को समाप्त करने में पुलिस का कार्य इस साल भी वैसा ही उल्लेखनीय रहा जैसा कि गुजरे सालों में। १९५९ के प्रारंभ में राज्य में सक्रिय डाकुओं के ९ दलों में से ६ को खत्म कर दिया गया है।

३५. पिछले सालों में जो पॉलिसी

Scanned by CamScanner

(श्री गुरमुखनिहालसिंह)

अपनाई गई और उनके फलस्वरूप जो कामयाबियां हमें मिलीं, उनसे राज्य में प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत हुई हैं और उनकी वजह से प्रजातन्त्र को आर्थिक व सामाजिक आधार मिला है। हमारे सामने जो कार्य अभी करने को हैं वे बहुत बड़े हैं और उनको पूरा करने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्प, त्याग, अनुशासन तथा सम्मिलित प्रयास आवश्यक है। यही एक ऐसा रास्ता है जिससे राज्य के जन-जीवन में प्रजातन्त्र का सच्चा स्वरूप दिखाई देगा।

३६. राज्य के निर्माण में उत्तरोत्तर हमारी महान जन-शक्ति का उपयोग किया जायगा और इसके लिए अत्यधिक प्रशासनिक कार्य-कुशलता अपेक्षित होगी। अतः यह आवश्यक है कि विकास कार्यक्रम को शीघ्र सम्पन्न करने की भावना जाग्रत की जाय और कार्य प्रणाली को सरल बनाया जाय ताकि राज्य की जनता राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के सारे कार्यों में स्वेच्छा से हाथ बटायें और इस कार्य को अपना समझ कर इसे सम्पन्न करने में अपना गौरव समझें।

३७. मुझे पूरा विश्वास है कि सदन में आप अपने विचार विमर्श में बुद्धिमत्ता व सहयोग की भावना से प्रेरित होंगे।

Scanned by CamScanner

Page No.9

संक्षिप्त–विवरण

(२४ फरवरी, १९६०)

स्कम्भ

राजस्थान के राज्यपाल, श्री गुरमुखनिहालसिंह, का अभिभाषण (१–१६)

११ बज कर ५ मिनिट मध्यान्ह पूर्व राज्यपाल महोदय ने सभा भवन में पदार्पण कर इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्यों के समक्ष कृपा पूर्वक अपना अभिभाषण दिया।

स्कम्भ

शुक्रवार, दिनांक २६ फरवरी, १९६० की कार्य–सूची

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं वाद–विवाद।

Scanned by CamScanner